



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]
No. 168]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2006/श्रावण 4, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2006/SRAVANA 4, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना (निर्णायक समीक्षा)

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2006

विषय :— चीन जन. गण. मूल के या वहाँ से निर्यातित पैरासिटामोल के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।

सं. 15/20/2006-डीजीएडी.— यतः 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पांटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पैरासिटामोल के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 22 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं.60/1/2000-डीजीएडी और दिनांक 17 मई, 2005 की संशोधन अधिसूचना द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम को अधिसूचित किया था ।

और यतः दिनांक 27 मार्च, 2002 और 19 जुलाई, 2005 की सीमाशुल्क अधिसूचना द्वारा संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच और वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित पैरासिटामोल है, जिसे एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है। पैरासिटामोल एक कार्बनिक रसायन है। यह एक भिर्गन्ध रहित दानेदार पाउडर होता है जिसका रासायनिक फार्मूला सी₉एच₉एनओ₂ है। यह एक बल्क भेषजीय सक्रिय तत्व है। यह पीड़ाहारी एवं ज्वरहारी गुणधर्मी वाला होता है और इसे पाउडर, दाना, इंजेक्शन और टैबलेट स्वरूपों में अनेक आरएक्स और ओटीसी औषध नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता है।

पैरासिटामोल को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार 2922.29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

3. जांच की शुरुआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 और उसके अंतर्गत बनाई गई पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जानी अपेक्षित है। प्राधिकारी का मानना है कि यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के प्रावधानों के तहत इस स्तर पर सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करना उचित होगा।

मै0 श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल्स लि0 हैदराबाद, मै0 फार्मसन एनाल्जेसिक्स, वडोदरा और मै0 भारत केमिकल्स, मुम्बई ने चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की आवश्यकता का प्रमाण देते हुए एक याचिका दायर की है और ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं के तहत संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को आगे और 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

4. शामिल देश:

वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण. है।

5. समीक्षा का आधार

याचिकाकर्ता ने चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानते हुए विक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को जोड़ने के पश्चात परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा किया है। आईबीआईएस, मुम्बई से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा निर्यात कीमत का दावा किया गया है। निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, निर्यात के देश में अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन हैंडलिंग और पत्तन प्रभार, कमीशन इत्यादि के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है।

जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया, उत्पादन की परिकलित लागत और निर्यात कीमत संबंधी सूचना, याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लिए दावा किए गए समायोजनों के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है और यह इस तथ्य पर आधारित है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद पाटन जारी रहा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता का कहना है कि क्षति की समाप्ति मुख्यतः पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण हुई थी और शुल्क को हटा लिए जाने से चीन जन.गण. से पाटित कीमतों पर अत्यधिक मात्रा में पुनः आयात होने लगेगा और इससे घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है। याचिकाकर्ता ने आगे यह आरोप लगाया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया जाता है तो आगे और क्षतिकारी पाटन होने की संभावना है क्योंकि संबद्ध देश में अप्रयुक्त क्षमता होने के कारण वर्तमान आयातों में वृद्धि होने की संभावना है।

6. क्रियाविधि

दिनांक 22/01/2002 की अधिसूचना सं. 60/1/2000-डीजीएडी के तहत अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम तथा दिनांक 27/3/2002 की अधिसूचना द्वारा लागू अंतिम शुल्क की समीक्षा का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पैरासिटामोल के आयात के संबंध में इस बात की समीक्षा करने के लिए एतद्वारा जांच शुरू करते हैं कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है अथवा नहीं।

समीक्षा में दिनांक 20/01/2001 की अधिसूचना सं. 60/1/2000-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं। मै0 श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल्स लि0 ने मूल जांच में भी घरेलू उद्योग की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी का उपर्युक्त नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग मानने का प्रस्ताव है जिनका भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है।

7. जांच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 (12 महीने) तक की है। तथापि क्षति विश्लेषण में वर्ष 2002-2003 से वर्ष 2005-2006 की अवधि शामिल होगी।

8. सूचना प्रस्तुत करना:

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों/उच्चायोगों/प्रतिनिधियों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में उनके संबद्ध ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को संगत सूचना, निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित पद्धति में प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)
क.सं. 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली - 110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

9. समय सीमा:-

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपर्युक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिन (40 दिन) के भीतर पहुँच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION (SUNSET REVIEW)

New Delhi, the 25th July, 2006

Subject : Initiation of Sunset Review on anti-dumping duty imposed on imports of Paracetamol originating in or exported from China PR.

No. 15/20/2006-DGAD.— Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as AD Rules), vide Notification Number 60/1/2000-DGAD dated 22nd January 2002, and Amendment Notification dated 17th May, 2005- the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive antidumping duty on import of Paracetamol (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as subject country).

And whereas definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification dated 27th March, 2002 and 19th July 2005.

2. Product Under Consideration

The product involved in the original investigation and this current review is Paracetamol, also known as Acetaminophen, originating in or exported from China PR. Paracetamol is an organic chemical, an odourless white crystalline powder, with chemical formula $C_8H_9NO_2$. It is a bulk pharmaceutical active ingredient, displaying analgesic and antipyretic properties and is used in a number of Rx and OTC drug formulations in the form of powders, granules, injectibles and tablets.

Paracetamol is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 2922.29 as per International Trade Classification. The

2271 GI/06-2

classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

3. **Initiation**

The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the AD Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. The Designated Authority considers that the sunset review of the anti dumping duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended.

M/s. Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd., Hyderabad, M/s Farmson Analgesics, Vadodara, and M/s Bharat Chemicals, Mumbai have jointly filed an application substantiating the need for sunset review of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from China PR and have requested for continuation and enhancement of the anti-dumping duty imposed on subject goods under the above mentioned notifications for a further period of 5 years.

4. **Country(ies) Involved:**

The country involved in the present investigations is China PR.

5. **Grounds for Review**

The applicant has claimed normal value of subject goods in China PR on the basis of constructed cost of production after addition for selling, general and administrative expenses treating China PR as non-market economy. The export price has been claimed on the basis of data provided by the applicant from IBIS, Mumbai. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation in the country of exports, port handling and port charges, commissions etc. to arrive at the net export price.

For the purpose of initiation, the Authority has prima facie, considered the normal value of the subject goods in the subject country on the basis of constructed cost of production and information on the export price, the adjustments claimed for the subject goods from the subject country as made available by the petitioner.

The request is for continuation and enhancement of the antidumping duties in force and is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of antidumping duty on import of the subject goods from the subject country. In addition the applicant alleges that the removal of injury was mainly due to the existence of anti-dumping duty and revocation of duty would lead to recurrence of substantial imports at dumped prices from China PR and would be likely to lead to a recurrence of injury to the domestic industry. The applicant has further alleged likelihood of further injurious dumping if the anti-dumping duty be allowed to lapse, as the current imports may be likely to increase due to existence of unused capacity in the subject country.

6. **Procedure:**

Having decided to review the final findings notified vide No. 60/1/2000-DGAD dated 22/1/2002 and final duty imposed by Notification dated 27/3/2002, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of antidumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury on imports of Paracetamol originating in or exported from China, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and AD Rules.

The review covers all aspects of Notification No.60/1/2000-DGAD dated 30/1/2001. M/s. Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd., have represented on behalf of the domestic industry in the original investigations also. The Authority proposes to consider the applicants, who constitute a major proportion of the production of the subject goods in India, as domestic industry in accordance with the Rules supra.

7. **Period of Investigation:**

The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 2005 to 31st March, 2006 (12 months). However, injury analysis shall cover the years from 2002-03 to 2005-06.

8. **Submission of Information:**

The exporters in the subject country, their government through their Embassies/High Commissions in India/representatives, the importers and

users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

9. **Time Limit:**

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

10. **Inspection of Public File:**

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority